तिब्बत देश

तिब्बती जनता का लोकतांत्रिक हथियार

निर्वासन में रहने वाला तिब्बती समाज इन दिनों अपने लिए नए प्रधानमंत्री और नई संसद के चुनाव में व्यस्त है। 1959 में तिब्बत पर चीन का कब्जा पूरा होने के बाद यह चौदहवां मौका है जब तिब्बती शरणार्थी लोकतांत्रिक चुनाव के रास्ते अपनी 'निर्वासन सरकार' का नेतृत्व चुनने जा रहे हैं। तिब्बत के इतिहास में यह तीसरी मौका होगा जब प्रधानमंत्री का चुनाव आम नागरिक के वोट के माध्यम से किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रेक्षकों के लिए यह प्रक्रिया कई मायनों में कौतुहल भरी है। पहली तो यह कि पिछली कई सदियों के लोकतांत्रिक इतिहास में पूरी दुनिया में केवल तिब्बत एक ऐसा देश है जिसका शरणार्थी समाज अपने लिए एक 'सरकार' का चुनाव करता है। ये चुनाव गुप्त मतदान के आधार पर होते हैं जिनका संचालन ठीक वैसे लोकतांत्रिक तरीके से होता है जैसा किसी भी अच्छे लोकतांत्रिक देश में होता है। बाहरी लोगों के लिए यह बात काफी रोचक होगी कि इस 'निर्वासन सरकार' की 'प्रजा' की कुल संख्या डेढ़ लाख से भी कम है जो दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले (सवा अरब से ज्यादा) और सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश चीन से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही है।

इस चुनाव प्रक्रिया का एक और रोचक पहलू यह है कि चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता भारत के अलग–अलग कोनों में बसी शरणार्थी बस्तियों के अलावा अमेरिका, कनाडा और यूरोप से लेकर जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बीच दो दर्जन से भी ज्यादा देशों में बसे हुए हैं। संसद और प्रधानमंत्री के लिए होने वाला यह चुनाव दो चरणों में होता है। पहले 'प्राथमिक' चरण में मतदाता अपनी प्राथमिकता वाले प्रत्याशियों के नाम सुझाते हैं और दूसरे चरण में मुख्य प्राथमिकता पाने वाले प्रत्याशियों के बीच चुनाव के लिए अंतिम मतदान होता है।

कुल मिलाकर तिब्बती संसद के 44 स्थानों के लिए मतदान होता है। इनके अलावा जरूरत समझने पर दलाई लामा एक से तीन तक सांसदों का खुद नामांकन कर सकते है। 44 निर्वाचित स्थानों में से 10–10 स्थान तिब्बत के तीन मूल प्रांतों (ऊ–त्सांग, खम और आम्दो) के लिए, दो–दो स्थान चार बौद्ध और बॉन समुदायों के भिक्षुओं के लिए और दो–दो स्थान उत्तरी अमेरिका और यूरोप में रहने वाले तिब्बती नागरिकों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तीनों प्रांतों से कम से कम दो–दो महिला सांसदों का चुना जाना अनिवार्य है। 2001 में शुरू हुई व्यवस्था में कालोन ट्रीपा (प्रधानमंत्री) का चुनाव आम नागरिकों के सीधे मतदान से किया जाता है।

लोकतंत्र और चुनाव विशेषज्ञ इस बात पर हैरान हैं कि मतदान केंद्रों के बीच हजारों मील की दूरी के बावजूद हर बार ये चुनाव बिना किसी बड़ी समस्या के और पूरे पारदर्शी तरीके से संपन्न होते आ रहे हैं।

लेकिन दुर्भाग्य से इस बार 3 अक्तूबर को हुए प्राथमिक मतदान के बाद नेपाल सरकार ने चीन सरकार के कहने पर वहां कई मतपेटियों को जब्त कर लिया और उन्हें भारत में धर्मशाला ले जाने या गिनने से रोक दिया गया। उधर भूटान सरकार ने भी अपने कारणों से अपने यहां मतदान पूरा नहीं होने दिया।

लेकिन इन दो घटनाओं को छोड़ कुल मिलाकर इस बार के मतदान का पहला चरण काफी प्रभावशाली रहा। मतदान के योग्य लगभग 90 हज़ार शरणार्थियों में से 79 हज़ार ने चुनाव में भाग लेने के लिए अपना पंजीकरण कराया था। उनमें से 61 प्रतिशत ने मतदान में हिस्सा लिया। पहले चरण के दौरान हुए चुनाव प्रचार की अभूतपूर्व सरगर्मी और उम्मीदवारों के बीच बहसों के लंबे सिलसिले से शरणार्थी समाज के बीच पैदा हुई रुचि ने इस बार के चुनाव को पहले से कहीं ज्यादा रोचक बना दिया है। लोगों में चुनाव के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 मार्च के अंतिम मतदान में और अधिक मतदाता भाग लेंगे।

हालांकि 1951 में तिब्बत पर चीन के आरंभिक कब्जे से पहले लगभग पांच सौ साल तक वहां धर्म आधारित शासन प्रणाली रही है जिसमें दलाई लामा राष्ट्राध्यक्ष और धर्मगुरू दोनों पदों पर बैठता है। लेकिन 1959 में भारत में शरण लेने के बाद वर्तमान दलाई लामा ने देश की शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए 2 सितंबर 1960 को पहली संसद की स्थापना की। 1961 में उन्होंने तिब्बत का पहला लोकतांत्रिक संविधान चर्चा के लिए जारी किया और 10 मार्च 1963 के दिन 'भविष्य के तिब्बत' के लिए नए संविधान को स्वीकार किया गया और मतदान के आधार पर संसद के चुनाव की परंपरा शुरू हुई। बाद में 11वीं संसद ने संविधान को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाते हुए 'एग्ज़ाइल चार्टर' स्वीकार किया जिसके तहत केंद्र स्तर पर स्वतंत्र चुनाव आयोग और शरणार्थी बस्तियों के स्तर पर 65 क्षेत्रीय चुनाव आयोगों का गठन किया गया। अब न केवल धर्मशाला में स्थापित तिब्बत की 'निर्वासन सरकार' की संसद और प्रधानमंत्री का चुनाव आम तिब्बती नागरिकों के वोट से होता है बल्कि भारत, नेपाल, भूटान और दूसरे देशों में तिब्बती शरणार्थी अपनी स्थानीय असेंबलियों और प्रतिनिधियों का चुनाव लोकतांत्रिक रास्ते से करते हैं।

तिब्बत और सिंकियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) पर गैरकानूनी कब्जा जमाकर चीन ने दक्षिण एशिया और केंद्रीय एशिया में जो सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक पहल हासिल की है वह उसके विश्व विजय के उपनिवेशवादी सपने का मूल आधार है। इस आधार को वह किसी भी कीमत पर खोने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान का सवाल उठते ही बीजिंग के नेता बौखला जाते हैं। इन दोनों देशों पर पिछले 60 साल के औपनिवेशिक नियंत्रण के बावजूद चीनी शासक बौद्ध तिब्बतियों और मुस्लिम उइगुर जनता को पालतू बनाने में बुरी तरह नाकामयाब रहे हैं। सैनिक और राजनीतिक दमन का हर हथकंडा इस्तेमाल करने बाद भी वे यह देख कर परेशान हैं कि इन देशों की जनता चीनी गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दलाई लामा की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता और तिब्बत के समर्थन में दुनिया भर में उभर रहे जन समर्थन ने तो चीन सरकार की चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

ऐसे में अब बीजिंग के कम्युनिस्ट शासकों की नई नीति इस उम्मीद पर टिकी हुई है कि दलाई लामा का जीवनकाल समाप्त होने पर तिब्बती आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाएगा और बीजिंग सरकार अपने एक पिठ्ठू को नया दलाई लामा घोषित करके तिब्बत समस्या को हल कर लेगी। लेकिन चीनी नेता यह भूल रहे हैं कि दलाई लामा पिछले पचास साल से जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खड़ा करने में लगे हुए हैं वह चीन के ऐसे हथकंडों का जवाब देने के लिए काफी है।

चीन और तिब्बत के बीच 60 साल से चल रहे विवाद की बारीकियों से बेखबर कुछ लोगों को तिब्बती शरणार्थी समाज की यह चुनाव व्यवस्था महज एक 'स्टॉर्म इन द कप' (कुल्लहड़ में तूफान ?) जैसा एक अर्थहीन प्रयास लग सकती है। लेकिन दलाई लामा के नेतृत्व में भारत के एक पहाड़ी कोने में चलने वाला यह प्रयास महज कुछ सांसदों या उनका नेता चुनने तक सीमित नहीं है। तिब्बती व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण में तिब्बत और चीन के भविष्य को दिशा देने वाले कई बीज छिपे हैं। अब चुनी गई संसद और प्रधानमंत्री सीधे खुद ही निर्वासन सरकार चलाते हैं। सोची समझी रणनीति के तहत दलाई लामा पांच दशक से धीरे–धीरे अपने अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की निर्वासन सरकार को सौंपते आ रहे हैं। निर्वासन में आम तिब्बती शरणार्थियों द्वारा लोकतांत्रिक चुनाव के रास्ते अपनी सरकार चुनने का यह कदम न केवल लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था और एकता का प्रमाण है बल्कि तिब्बत के स्वतंत्रता संग्राम को लंबे समय तक और प्रभावी ढंग से चलाते रहने का औज़ार भी है।

– विजय क्रान्ति

भारतीय संसद ने सोवा–रिग्पा को मान्यता देने के लिए एक विधेयक पारित किया

भारत ने चीन के द्वारा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान में दो परमाणु संयंत्र लगाने में सहयोग का भी विरोध करने का निर्णय लिया है।जानकारों ने कहा कि भारत एनएसजी सदस्यों से इस विषय पर बात करेगा। एनएसजी परमाणु प्रसार के सख्त खिलाफ है।

(तिब्बत डॉट नेट, 1 सितंबर, धर्मशाला) भारतीय संसद की राज्य सभा ने चिकित्सा की सोवा–रिग्पा पद्धति को भारतीय चिकित्सा पद्धति की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए 25 अगस्त को एक विधेयक पारित किया। इससे पहले इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (एमेंडमेंट) बिल, 2010 पर लोक सभा में चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सोवा–रिग्पा पद्धति प्रचलित है, वहां इसे मुख्यधारा में शामिल करने का सरकार प्रयास करेगी। यह विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया था। आजाद ने कहा कि सोवा–रिग्पा की चिकित्सा पद्धति उपहिमालय क्षेत्रों और तिब्बत, मंगोलिया, जापान आदि कुछ देशों से सटे इलाकों में प्रचलित है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से इस प्रचीन चिकित्सा पद्धति के संरक्षण और विकास में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह सोवा–रिग्पा के शिक्षण और पेशेवर इस्तेमाल को भी नियमित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए एक आयोग बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें सोवा–रिग्पा को भी शामिल किया जाएगा। इस विधेयक के पारित होने से जहां इस क्षेत्र में शिक्षण की एक न्यूनतम मानक की स्थापना होगी वहीं सोवा रिग्पा चिकित्सा पद्धति के सभी चिकित्सकों का पंजीकरण किया जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर में चीनी भूमिका से भारत चौकस

(टीएनएस, 1 सितंबर, नई दिल्ली)

जम्मू और कश्मीर और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती अभिरुचि से भारत सावधान हो गया है और वह अब चीन को रोकने के उपाय सोचने लगा है। भारत तिब्बत पर मुखर रुख अपनाने और पाकिस्तान के साथ चीन के गुप्त परमाणु सहयोग को उजागर करने के बारे में सोच रहा है। पिछले दिनों सुरक्षा पर मंत्रीमंडलीय समिति की बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानने वाले एक सूत्र के मुताबिक भारत की संप्रभुता खासकर जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के प्रति चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए भारत बहुमुखी रणनीति पर विचार कर रहा है। नई दिल्ली ने चीन को यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू–कश्मीर पर उसकी हालिया कार्रवाई भारत की ओर से सीमा विवाद के बावजूद संबंधों को सामान्य बनाने के लिए की जा रही कोशिशों के अनुकूल नहीं है।

जानकारों ने कहा कि भारत इस रुख पर दृढ़ रहेगा कि चीन के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. जसवाल को वीसा नहीं मिला तो भारत चीन से किसी प्रकार का सैन्य सहयोग नहीं रखेगा। जसवाल चीन की पूर्व निर्धारित यात्रा पर जाने वाले थे। चीन ने जसवाल के जम्मू–कश्मीर का सैन्य अधिकारी होने के कारण वीसा देने से इंकार कर दिया था। बदले में भारत ने सैन्य वार्ता रोक दिया और तीन चीनी सैन्य अधिकारियों को वीसा देने से इंकार कर दिया, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारत आने वाले थे। दोनों देशों के अधिकारियों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पूर्व में एक साथ कई छोटे–छोटे संयुक्त सैन्य अभ्यास किए थे।

इस बीच भारत का एक उच्चस्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल सामरिक उपकरणों के विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए दक्षिण कोरिया पर यात्रा पर गया। दक्षिण कारिया से चीन के बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुआई रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत की रुचि उच्च स्तर के सामरिक उपकरणों के शोध में है, जिसे विकास करने का काम निजी कंपनियां करेंगी। दक्षिण कोरिया में कुछ कंपनियां रक्षा उपकरण बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। भारत ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर सकें। जानकारों का कहना है कि दक्षिण कोरिया की कुछ अग्रणी अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के पास जहाजों के निर्माण और प्रिसीजन इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी प्रौद्योगिकी है।

इसके अलावा साउथ ब्लॉक के कुछ अधिकारियों का मानना है कि भारत को तिब्बत और पाकिस्तान के साथ चीन के गोपनीय परमाण्विक सहयोग के बारे में सक्रिय होना चाहिए। अब तक भारत का रुख यह रहा है कि तिब्बत स्वायत्तशासी प्रदेश चीन का अभिन्न हिस्सा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा तिब्बत पर हमारे रुख को चीन हमारी कमजोरी नहीं समझे......अगर भारत तिब्बत की स्थिति पर सवाल करने लगे तो?

भारत ने चीन के द्वारा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान में दो परमाणु संयंत्र लगाने में सहयोग का भी विरोध करने का निर्णय लिया है। जानकारों ने कहा कि भारत एनएसजी सदस्यों से इस विषय पर बात करेगा। एनएसजी परमाणु प्रसार के सख्त खिलाफ है।

भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव में चीन की बढ़ती गतिविधियों से भी सतर्क हो गया है। विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने संसद में पिछले दिनों कहा कि प्रशांत महासागर में चीनी

गतिविधि सामान्य से कुछ अधिक है। उसकी मंशा पर नजर रखी जा रही है। भारत सरकार यह महसूस करने लगी है कि प्रशांत महासागर में चीनी गतिविधि सामान्य से अधिक है। इस साल जनवरी में भारत ने पूर्व के 12 पड़ोसी देशों के साथ अंडमान द्वीपसमूह के पास समुद्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। इनमें से कुछ देशों के साथ चीन के मधुर संबंध नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में चीन ने दो बार जम्मू–कश्मीर के भारत में विलय पर सवाल उठाया, जिससे भारत और पाकिस्तान के इस द्विपक्षीय मसले पर चीन का पाकिस्तान की ओर झुकाव का स्पष्ट पता चलता है। पिछले साल के आरंभ से चीन ने जम्मू–कश्मीर के निवासियों को पासपोर्ट पर नत्थी एक अलग कागज पर वीसा देना शुरू किया है।

'सभी धर्मों में सौहार्द को बढ़ावा देने की समान क्षमता है'

(टिबेट डॉट नेट, 5 सितंबर, 2010, धर्मशाला) शनिवार को कोच्चि में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संघ के 33वें विश्व कांग्रेस में अपने मुख्य संबोधन में परमपावन दलाई लामा ने कहा कि लोगों को अलग–अलग धर्मों के पालन की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी धार्मिक परंपराओं में सकारात्मक मानवीय मूल्यों का एकसमान संदेश मिलता है। पीटीआई की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। परमपावन ने कहा कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख आदि विभिन्न धर्मों के दर्शन और परंपराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन इन सबसे प्रेम, करुणा, सहनशीलता और संतोष का एकसमान संदेश मिलता है, इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, "अपने धर्म का पालन करें, लेकिन सभी धार्मिक परंपराओं का सम्मान करें। कुछ लोग धार्मिक विश्वास की गलत व्याख्या करते हैं जो काफी दुःखद बात है।" 21वीं सदी को संवाद की सदी बताते हुए परमपावन ने धार्मिक सौहार्द् को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न धर्मों के बीच संवाद की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि लोग अब चीन एवं रूस में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के लोग और वहां के वैज्ञानिक भी अब अध्यात्म में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा, "उपरी तौर पर वे नास्तिक हो सकते हैं, पर आंतरिक तौर पर वे धार्मिक हैं।" उन्होंने कहा कि दुनिया भर में खनिज संसाधनों के प्रति बेपरवाही और उनके दोहन ने पाकिस्तान, अफ्रीका के कई हिस्सों, चीन, तिब्बत और लद्दाख में बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं लाई हैं। उन्होंने कहा, "हमारे ग्रह के प्रति वैश्विक जिम्मेदारी के भाव का विकास करने की जरूरत है।"

इसके बाद एक पारस्परिक संवाद सत्र में उनसे एक महिला प्रतिनिधि ने पूछा कि संवाद की इस सदी में क्या वह महिलाओं के लिए कोई खास भूमिका देखते हैं। उन्होंने इसके जवाब में कहा, 'इस बारे में कोई संदेह नहीं है। जैविक रूप से महिलाओं में करुणा और प्यार बांटने की ज्यादा संभावना होती है। यहां तक कि जब पिता नहीं रहते हैं, मां सबकी देखभाल करते हैं। इसलिए महिलाओं को ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।"

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा में ज्ञान और बुद्धि विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा समग्र बनाने के लिए इसमें नीतिशास्त्र को शामिल करने की जरूरत है। इसके पहले दक्षिण भारतीय राज्य केरल के शहर कोच्चि में सुबह पहुंचने पर सैकड़ों तिब्बतियों और शुभेच्छुओं ने परमपावन का गर्मजोशी से स्वागत किया। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संघ के विश्व आयोजन स्थल पर भी परम पावन दलाई लामा का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। इसके बाद वहां जापान योग संघ के एक प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले 12 धर्मों की प्रार्थनाएं की गईं।

पिछले कुछ सालों में चीन ने दो बार जम्मू–कश्मीर के भारत में विलय पर सवाल उठाया, जिससे भारत और पाकिस्तान के इस द्विपक्षीय मसले पर चीन का पाकिस्तान की ओर झुकाव का स्पष्ट पता चलता है। उन्होंने कहा, "अपने धर्म का पालन करें, लेकिन सभी धार्मिक परंपराओं का सम्मान करें। कुछ लोग धार्मिक विश्वास की गलत व्याख्या करते हैं जो काफी दुःखद बात है।"

डॉक्टर, ब्यूटी क्वीन ने खून के साथ तिब्बती आंदोलन का समर्थन किया

(टीएनएन, 20 सितंबर, चंडीगढ़)

सही समय पर रक्तदान कर करीब 38 लोगों का जीवन बचाने का दावा करने वाले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने तिब्बतियों के अपनी मातृभूमि हासिल करने के आंदोलन करने का समर्थन करते हुए चीनी राष्ट्रपति के पोस्टर को खून के बूंदों से रंग दिया। डॉ. महेश यादव के इस प्रयास में मिस हिमाचल पूर्वा राणा ने भी सहयोग दिया। इस अवसर पर यादव ने कहा, "तिब्बत काफी समय से चीनी शासन के कब्जे में है और मैं इसकी आज़ादी के लिए लड़ रहा हूं। मैं यह काम भारत की सुरक्षा के लिए और मानवता की भलाई के लिए कर रहा हूं। तिब्बतियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह अनुचित है और अब समय आ गया है कि उन्हें न्याय दिया जाए।"

ब्यूटी क्वीन राणा ने कहा, "मैं धर्मशाला की रहने वाली हूं और मैंने यह देखा है कि चीन ने जो कुछ किया है उसका खामियाजा किस तरह से तिब्बतियों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूं और इस वजह से आज मैं यहा हूं।"

शनिवार को यहां के सेक्टर 15 में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में डॉ. यादव ने चीनी राष्ट्रपति

खबर में भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय वायुसेना ने न्योमा को एक पूर्ण हवाई अड्डे में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है जहां लड़ाकू विमानों सहित सभी तरह के विमानों की आवाजाही हो सके। खबर के अनुसार न्योमा हवाई पट्टी 13,300 फुट उंचाई पर स्थित चीनी कब्जे वाले तिब्बती सीमा पर स्थित नियंत्रण रेखा से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है।

हू जिनताओ के पोस्टर पर अपने खून पोत दिए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए अपने खून का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं किया है। उन्होंने कहा, "मैं तिब्बत के लिए पिछले 14 साल से आंदोलन कर रहा हूं और मैंने देश–विदेश में अपने खून से कई स्वतंत्रता सेनानियों के कई पोर्ट्रेट बनाए हैं। मैं देश के लगभग हर शहर में गया हूं और मैंने हाल में धर्मशाला में विरोध कार्यक्रम किया है। मैं महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का अनुयायी हूं और तिब्बत के लिए वैसा ही काम करना चाहता हूं जैसा उक्त महापुरुषों ने अपने देश के लिए किया। यह पूछने पर कि गांधी और मंडेला तो अहिंसा के रास्ते पर विश्वास करते थे तो वह विरोध प्रदर्शन के लिए खून का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यादव ने कहा, "मैं काफी समय से मानवाधिकार आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। मैंने रक्तदान कर 38 लोगों की जिंदगी बचाई है और अब अपने खून से पोर्ट्रेट बना कर तिब्बत में हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयास कर रहा हूं।" इस अवसर पर समर्थन जताने के लिए तिब्बती विद्यार्थी भी मौजूद थे। पंजाब विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस की प्रथम वर्ष की छात्रा तेनजिन डोलमा ने कहा, 'मैं तिब्बत में रहने वाले अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूं। उनको काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है और मुझे लगता है कि इस अभियान से उनको कुछ मदद मिल सकती है।" बी.ए. प्रथम वर्ष के छात्र फुंसूक दोरजी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा, "मुझे इस बात ने काफी प्रभावित किया है कि यादव और राणा इस तरह के अभियान में लगे हैं जबकि वे तिब्बती नहीं हैं। हमारे लोगों को हर वह मदद मिलनी चाहिए जिसके वे हकदार हैं। इस विरोध प्रदर्शन के तहत संयुक्त राष्ट्र को भेजी जाने वाली एक याचिका पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया जिसमें यह मांग की गई है कि चीन को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। यादव और राणा की योजना जल्दी ही दिल्ली जाने की है।

चीन से मुकाबले के लिए भारत सीमा पर स्थित हवाई पट्टियों को मजबूत कर रहा है

(टिबेटन रिव्यू डॉट नेट, 22 सितंबर)

भारत पूर्वी लद्दाख में स्थित न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) को एक पूर्व सुविधा वाले हवाई अड्डे में बदलने की तैयारी कर रहा है ताकि लद्दाख के सीमांत क्षेत्र को शेष भारत से बेहतर संपर्क बनाया जा सके और वहां पर्यटन एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया ऑनलाइन ने 21 सितंबर को यह खबर प्रकाशित की है। हालांकि, ऐसा लगता है कि इसके पीछे असल उद्देश्य चीन द्वारा 4,056 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तैयार किए जा रहे भारी सैन्य ढांचे का मुकाबला करना है। इस क्षेत्र में सड़क संपर्क विकसित होने और ऐसे एएलजी के विकास से भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान और चीन सीमा तक तैनाती में आसानी होगी। इस तरह के बुनियादी ढांचे से किसी भी आपात काल में तत्काल भारतीय सैनिकों को इस इलाके में पहुंचाया जा सकता है।

खबर में भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय वायुसेना ने न्योमा को एक पूर्ण हवाई अड्डे में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है जहां लड़ाकू विमानों सहित सभी तरह के विमानों की आवाजाही हो सके। खबर के अनुसार न्योमा हवाई पट्टी 13,300 फुट उंचाई पर स्थित चीनी कब्जे वाले तिब्बती सीमा पर स्थित नियंत्रण रेखा से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। न्योमा के साथ ही पिछले कुछ सालों में दौलत बेग ओल्दी और फ्यूकशे जैसे एएलजी का विकास किया गया है। इससे लद्दाख के सीमांत क्षेत्र देश की मुख्य धारा से बेहतर रूप से जुड़ सकेंगे और वहां पर्यटन एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

खबर के अनुसार पश्चिमी सेक्टर के एएलजी को फिर से सक्रिय करने के साथ ही भारतीय वायु सेना पूर्वी क्षेत्र में स्थित पैसीघाट, मेछुका, वलांग, तुतिंग, जाइरो और विजयनगर एएलजी और अरुणाचल प्रदेश में कई हेलीपैड को भी उन्नत बना रही है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा से सुरक्षित बचकर आए विधायक पीएम से मिलेंगे

(टीएनएन, काठमांडू, 22 सितंबर)

चीन नियंत्रित तिब्बत में भारी कठिनाइयों का सामना कर लौटे राजस्थान से भाजपा विधायक मोहन लाल गुप्ता कैलाश यात्रियों की दुर्दशा के मसले को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के सामने उठाने जा रहे हैं। गुप्ता भी उन तीर्थयात्रियों में शामिल थे जो खराब मौसम की वजह से तिब्बत में अमानवीय स्थितियों में फंस गए थे। बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे 55 साल के विधायक ने कहा, "चीन को भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कैलाश–मानसरोवर यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और भारतीय तीर्थयात्रियों को प्रताड़ना का पात्र नहीं बनाना चाहिए। चीन सरकार को इस यात्रा को आसान बनाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए और कुछ और परमिट देने चाहिए।" गुप्ता के साथ उनकी पत्नी, राजस्थान के 22 अन्य तीर्थयात्री और छत्तीसगढ़ के पांच तीर्थयात्री थे। वे सब लोग 7 सितंबर को हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों के पवित्रतम तीर्थ कैलाश–मानसरोवर की यात्रा पर रवाना हुए थे। वे यात्रा पूरी करने के बाद पिछले हफ्ते जब

वे वापस लौट रहे थे तो खराब मौसम की वजह से वे तिब्बत के एक सीमावर्ती कस्बे में फंस गए और पांच दिन तक वहीं पड़े रहे। गुप्ता ने बताया, "हमारे समूह में शामिल छह लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। वे पहले से ही ऊंचे अक्षांश पर होने वाली मुश्किलों की वजह से कमजोर हो गए थे। लेकिन उन लोगों को चिकित्सा सुविधा देना तो दूर उन्हें एक पुलिस थाने में बिठाकर रखा गया। कुछ लोगों को तो एक हफ्ते तक जंगल में रहना पड़ा।" तीर्थयात्रियों को एक बार ही चीन में प्रवेश करने के लिए एंट्री वीजा दिया गया था, इसलिए चीनी अधिकारियों ने उन्हें वापस ल्हासा नहीं जाने दिया, जबकि उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा दिए जाने की जरूरत थी और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। गुप्ता ने बताया, "खराब मौसम की वजह से हमें अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा, लेकिन हर बार और हर छोटी चीज के लिए, जैसे कैलाश पर्वत के नजदीक राम–लक्ष्मण मंदिर के दर्शन के लिए हमें अधिकारियों से अलग–अलग इजाजत लेनी पड़ी। चीनी सबसे ज्यादा गैर दोस्ताना व्यवहार करते हैं, हमें प्रताड़ित किया गया, हमारे सामान की कठोरता से जांच की गई। यह मेरे जीवन का सबसे खराब अनुभव था।" चीन से कोई मदद न मिलने के बाद गुप्ता ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत से संपर्क किया जिन्होंने तत्काल नेपाल में भारतीय राजदूत राकेश सूद से संपर्क किया। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। आखिरकार सोमवार को जब मौसम थोड़ा सुधरा तो गुप्ता के समूह के साथ ही आंध्र प्रदेश, मुंबई और ब्रिटेन के अन्य तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर से नेपाल सीमा तक पहुंचाया गया। वहां से कुछ बहुत ज्यादा थक चुके यात्री काठमांडू चले गए और बाकी लोग नेपालगंज होते हुए सड़क मार्ग से भारत पहुंच गए। हालांकि, मंगलवार को काठमांडू पहुंचे गुप्ता का नेपाल के मारवाड़ी समुदाय में हीरो की तरह स्वागत किया गया। उनके लिए बुधवार को एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। तिब्बत के बहुत उंचाई पर होने, बहुत ज्यादा टंड पड़ने, अनिश्चित मौसम और द्वेषपूर्ण अधिकारियों की वजह से तीर्थयात्रियों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ा। चीन वैसे तो तिब्बत को पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा कर चुका है, लेकिन यात्रियों को लेकर चीन का व्यवहार अभी भ्रमित करने वाला ही है। ल्हासा और काठमांडू के बीच एक सीधी बस सेवा शुरू की गई है जो नेपाल एवं चीन सरकार द्वारा मिलकर संचालित की जाती है। लेकिन चीनी प्रशासन द्वारा खासकर किसी समूह में न जाने वाले यात्रियों को वीजा देने में आनाकानी से इस बस सेवा को कई बार रोका गया है।

परम पावन दलाई लामा ने लद्दाख के बाढ़ पीड़ितों को सांत्वना दिया

(टिबेट डॉट नेट, 14 सितंबर, धर्मशाला)

परम पावन दलाई लामा ने लेह में आए विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सोमवार को प्रार्थना की। वे बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित चोगलमसर के पुनर्वास शिविर के दौरे पर गए। परमपावन के साथ जम्मू–कश्मीर के मंत्री गवांग रिगजिन जोरा भी थे। चोगलमसर के बाद परमपावन दलाई लामा लेह में बौद्धों के मुख्य मठ जोखांग भी गए और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए वहां प्रार्थना की। इसके बाद लामदोन स्कूल मैदान पर जुटी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए परमपावन ने बाढ़ से बचे लोगों को ढाढस बंधाते हुए एक नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया और आह्वान किया कि हर व्यक्ति दिन भर में कम से कम 1 लाख से 6 लाख बार तक मनि (बौद्ध धार्मिक मंत्र) का जाप करे। उन्होंने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा कि जब उनकी मां का निधन हो गया था तो वे दिन भर में 6 लाख बार मनि का जाप करते थे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि वे परेशान न हों और इस आपदा में जान गवां देने वाले अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना करें। परम पावन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए दान दिया।

अमेरिका ने तिब्बत के योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित किया

(सिफी डॉट कॉम, 16 सितंबर)

तिब्बत में चीनी हमले और उसे अपने कब्जे में लेने के विरोध में करीब 15 साल तक जमकर गुरिल्ला युद्ध करने वाले सैकड़ों तिब्बती योद्धाओं की याद में अब एक स्मारक बनाया गया है जो चीन सरकार के माथे पर शिकन डाल सकता है। इन गुरिल्ला योद्धाओं को अमेरिकी की खुफिया एजेंसी सीआईए ने प्रशिक्षण दिया था और हथियार मुहैया कराए थे। अमेरिका ने पहली बार इन लड़ाकों को श्रद्धांजलि दिया है और यह स्वीकार किया है कि उनको सीआईए ने प्रशिक्षण दिया था। अमेरिका ने इन लड़ाकों की याद में कैम्प हेल में एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया गया। कोलोराडो में स्थित कैम्प हेल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों का एक प्रशिक्षण केंद्र था। स्थानीय लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि वहां कोई सैन्य प्रशिक्षण केंद्र है, लोग इसे एक परमाणु परीक्षण केंद्र के रूप में जानते थे। कैम्प हेल में सीआईए द्वारा 1957 से 1972 के दौरान करीब 2000 तिब्बती योद्धाओं को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। इन योद्धाओं को चीन जनमुक्ति सेना के जवानों के खिलाफ लड़ने

चीन से कोई मदद न मिलने के बाद गुप्ता ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत से संपर्क किया जिन्होंने तत्काल नेपाल में भारतीय राजदूत राकेश सूद से संपर्क किया। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। आखिरकार सोमवार को जब मौसम थोड़ा सुधरा तो गुप्ता के समूह के साथ ही आंध्र प्रदेश, मुंबई और ब्रिटेन के अन्य तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर से नेपाल सीमा तक पहुंचाया गया।

चीन अफ्रीका के लिए अपने तरीके तब तक नहीं बदल सकता, जब तक वह चीन में अपने तरीके नहीं बदलता। चीन तब तक चीन में अपने तरीके नहीं बदल सकता जब तक तिब्बत में अपने गलत कार्यों को सही ठहराता है। तिब्बत आज इतिहास के एक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। दुनिया भर के लोकतंत्र समर्थकों को फिर उसी तरह एक करना चाहिए, जैसे दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेद भाव की नीति (एपार्थीड) के खिलाफ वे एक हुए थे।

का प्रशिक्षण दिया गया जिन्होंने 1949 में तिब्बत पर हमला किया और इसके दो साल के भीतर इस बौद्ध देश को चीन में मिला दिया गया।

पिछले हफ्ते कोलोराडो के कैम्प हेल में आयोजित एक समारोह में चीनी सैनिकों के खिलाफ अभियान में शामिल तिब्बती, सीआईए के पूर्व एजेंट, अमेरिकी वन सेवा के अधिकारी और तिब्बती–अमेरिकी समुदाय के कई प्रमुख लोग जुटे। इस अवसर पर जिन स्मारक पट का अनावरण किया गया उस पर लिखा है, "साल 1958 से 1964 तक कैम्प हेल ने तिब्बती स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रशिक्षण स्थल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीआईए से प्रशिक्षण हासिल करने वाले कई बहादुर तिब्बती स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी जान गवां बैठे। वे अपनी पीढ़ी के सबसे अच्छे और बहादुर लोग थे और जब अपने देश के नागरिकों के लिए लड़ते समय उनकी जान चली गई थी तो हम सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह पट्टिका उनकी याद को समर्पित है।"

जब मोआत्से तुंग के शासन काल में चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो अमेरिकी सरकार ने तिब्बतियों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया और उन्हें हवाई जहाज से चीनी कब्जे वाले तिब्बत में पहुंचा दिया, क्योंकि वह बीजिंग को साम्यवाद का संभावित निर्यातक मानता था और उसे इस क्षेत्र में अमेरिकी गठबंधन और हितों के लिए खतरा मानता था। इन गुरिल्ला सैनिकों को भारत सरकार का भी समर्थन हासिल था। इनमें से कई ने तिब्बत की सीमा पर स्थित नेपाली जिले मुस्तांग में रहकर अपना अभियान चलाया।

न्यूयॉर्क के इंटरनेशल कैंपेन फॉर टिबेट (आईसीटी) ने इस बारे में कहा, "कई दूसरे सीआईए अभियानों की तरह ही तिब्बती गुरिल्लाओं के साथ अमेरिकी संपर्क, उनको कैम्प हेल में प्रशिक्षण देने की बात पहले अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब उस दौर के इतिहास को अमेरिकी और तिब्बती अकादमिक विद्वानों, पत्रकारों और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उनके द्वारा लगातार लिखा जा रहा है। आईसीटी में सरकारी संपर्क विभाग के निदेशक टॉड स्टीन ने कहा, 'हम सीनेटर मार्क उडाल की इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में इस बात के लिए अगुवाई की और तिब्बतियों की आज़ादी के लिए अमेरिका के ऐतिहासिक समर्थन और अपने देश के लिए लड़ने वाले बहुत से तिब्बतियों द्वारा प्रदर्शित साहस को समुचित मान्यता दिलाने के लिए अमेरिकी वन सेवा के साथ मिलकर कार्य किया।"

लेकिन तिब्बतियों योद्धाओं को यह श्रद्धांजलि बीजिंग के माथे पर शिकन बढ़ा सकता है जो अब भी मुस्तांग को ऐसे केंद्र के रूप में शक भरी नजरों से देखता है जहां फिर से तिब्बत की आज़ादी का आंदोलन शुरू हो सकता है और चीन ने सीमा क्षेत्र में गश्त तेज करने का अभियान शुरू किया है। चीन ने उन तिब्बती शरणार्थियों को नेपाल में शरण दिलाने के अमेरिकी प्रयासों को भी रोका है जिन्हें अक्सर नेपाल पुलिस द्वारा पकड़कर चीनी सैनिकों को सौंप दिया जाता है। तिब्बती लड़ाकों का यह प्रतिरोध तब जाकर बंद हुआ जब 1959 में ही निर्वासित होकर भारत आने वाले तिब्बती शासक दलाई लामा ने उन्हें इसे रोकने का संदेश भेजा।

दक्षिण अफ्रीकी पार्लियामेंट में सांसदों ने तिब्बत पर बयान दिया

(टिबेट डॉट नेट, प्रीटोरिया, 17 सितंबर)

निर्वासन में तिब्बती लोकतंत्र के 50 साल पूरा होने पर दक्षिण अफ्रीकी सांसदों ने 14 सितंबर को तिब्बत, चीन और परमपावन दलाई लामा पर चार बयान दिए और संसद में इस पर बहस आयोजित की गई। इस बहस की अध्यक्षता संसद के अध्यक्ष मैक्स सिसुलु ने की और इसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। दोपहर के इस खास सत्र को देखने के लिए तिब्बती पारंपरिक गलाबंद (खाता) पहने हुए अस्सी से ज्यादा सांसद और साउथ अफ्रिकन फ्रेंड्स ऑफ टिबेट (एसएएफटी) के नेतृत्व में करीब सौ तिब्बत समर्थक मौजूद थे।

इस अवसर पर आईएफपी सांसद मारियो एम्ब्रोसिनी ने अपने बयान में कहा, "ऐसे समय में भी हम तिब्बतियों के दोस्त और चीन के दोस्त के रूप में खड़े रहे हैं जबकि चीन अफ्रीका के लिए नई मुश्किलें खड़े कर रहा है। चीन अफ्रीका के लिए अपने तरीके तब तक नहीं बदल सकता, जब तक वह चीन में अपने तरीके नहीं बदलता। चीन तब तक चीन में अपने तरीके नहीं बदल सकता जब तक तिब्बत में अपने गलत कार्यों को सही ठहराता है। तिब्बत आज इतिहास के एक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। दुनिया भर के लोकतंत्र समर्थकों को फिर उसी तरह एक करना चाहिए, जैसे दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेद भाव की नीति (एपार्थीड) के खिलाफ वे एक हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि तिब्बती वहीं मांग रहे हैं, जो समस्त चीनियों को भी चाहिए– न्यूनतम स्वायत्तता और सभी मूलभूत अधिकार, जिसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में किया गया है। तिब्बत मसले पर पांचवें अंतराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में भी तिब्बतियों की इस मांग का समर्थन किया गया था।

डेमोक्रेटिक एलायंस की सांसद संतोष विनीता कल्याण ने कहा कि दलाई लामा को उनकी मर्जी से जब वे चाहें दक्षिण अफ्रीका आने के लिए वीजा दिया जाए। फ्रीडम फ्रंट के सांसद कोर्न मुल्डर ने कहा कि वे

एएनसी के प्रतिनिधियों को आज ही संसद में बुलाना चाहेंगे और उनसे अपील करेंगे कि तिब्बत में चीनियों के मानवाधिकार उल्लंघन के विराध में और तिब्बतियों के आत्म निर्णय के लिए समर्थन दें।

इस कुछ ही समय पहले आईएफपी के नेता प्रिंस मंगोसुथु बुथेलेजी ने स्थानीय मीडिया को कहा कि ''तिब्बत का मसला सिद्धांत पर आधारित है और यह बस लोकप्रियता या मत हासिल करने का कोई तरीका नहीं है। पूरा जीवन मैंने सही बात का साथ दिया है चाहे इसके लिए मुझे निजी या राजनीतिक तौर पर भले ही कोई नुकसान हुआ हो।'' उन्होंने कहा कि यदि हम तिब्बतियो की स्वायत्तता के समर्थन में और उन पर हो रही ज्यादती के विरोध में आवाज नहीं उठा सकें, तो मानना चाहिए कि खुद हमारा लोकतांत्रिक जीवन खतरे में है।

(तिब्बत कार्यालय, प्रीटोरिया से भेजी रिपोर्ट)

संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा सत्र के बाद तिब्बत में पर्यावरण का मसला उठाया गया

(टिबेट डॉट नेट, 30 सितंबर, जेनेवा)

जेनेवा में 27 सितंबर को आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 15वें सत्र के मौके पर एक प्रजेंटशन में तिब्बती पर्यावरण के एक विशेषज्ञ श्री तेनजिन नोर्बू ने कहा, "तिब्बत का पठार दुनिया के सबसे संवदेनशील पर्यावरण क्षेत्रों में से है और यह एक विशिष्ट जैव–भौगोलिक क्षेत्र है।" उन्होंने कहा, "लेकिन यह पठार वैश्विक औसत से तीन गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 साल में करीब तिब्बती हिमनदियों का करीब 20 फीसदी हिस्सा पीछे खिसक चुका है।" जेनेवा में चल रहे मानवाधिकार परिषद के 15वें सत्र के अवसर पर नोर्बू ने यह बात कही। नोर्बू भारत के धर्मशाला शहर में स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पर्यावरण एवं विकास डेस्क के प्रमुख हैं। उन्होंने तिब्बत के पठार से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं का विस्तृत खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दुष्प्रभावों से न सिर्फ तिब्बती पठार पर रहने वाले 60 लाख तिब्बतियों को समस्या हो रही है बल्कि इससे भारत, चीन और अन्य पड़ोसी देशों के अरबों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन सरकार द्वारा तिब्बत पठार के यारलुंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र), ड्रि चु (यांगजे) और सालवीन नदियों पर गोपनीय तरीके से बनाए जा रहे बांधों की वजह से वियतमान, लाओस, कंबोडिया, पाकिस्तान, बर्मा और भारत में निचली धाराओं के पास रहने वाले करोड़ों लोगों और जैवविविधता पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संबंधित देश या अंतरराष्ट्रीय समुदाय तिब्बत के पर्यावरण की रक्षा करने में विफल रहता है तो भविष्य में जल सुरक्षा पर भारी खतरा पैदा हो सकता है। श्री तेनजिन नोर्बू ने अपने 45 मिनट के प्रजेंटेशन में चार मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया जिनका जलवायु परिवर्तन की वजह से तिब्बत के पठार पर सीधा असर पड़ने वाला है। पहला, तिब्बत के पठार पर हिमनदियों का पीछे हटना। दूसरा, तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियों और उन पर बनने वाले बांध का मसला। तीसरा, तिब्बत के पठार पर परमाफ्रॉस्ट का पिघलना और दुनिया पर इसका असर। चौथा, घुमंतू यानी खानाबदोश जातियों को उनके पुश्तैनी चारागाहों से हटाकर शहरों में बसाने का दुष्प्रभाव।

उन्होंने कहा कि चीन सरकार ने जबरन सात लाख तिब्बतियों खानाबदोशों को उनके पुश्तैनी जमीन से हटाकर पर्यावरण संरक्षण के बहाने कॉन्क्रीट की इमारतों में डाल दिया है। हालांकि, इसके विपरीत चीन की सरकारी कंपनियां और कुछ निजी कंपनियां तिब्बती पठार पर बड़े पैमाने पर खनन परियोजनाओं के लिए सक्रियता से निवेश कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हाल में सिचुआन प्रांत के कार्जे तिब्बती स्वायत्तशासी प्रशासन में स्थित पालयुल के नागरिकों ने खनन परियोजना के विरोध में धरना दिया और उनकी शिकायतों को सुनने की जगह पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी जिससे कई तिब्बती नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने बताया कि ठंडे और कठोर मौसम के बावजूद तिब्बती खानाबदोश लोगों का समूह इस पठार पर पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना कर रहता है। श्री माइकल बकले द्वारा निर्देशित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'द मेल्टडाउन इन टिबेट' में कई ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें दिखती हैं जिनसे पता चलता है कि चीन सरकार बांध बनाने को लेकर किस तरह से पागल हुई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र के समानांतर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अमेरिका, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय के करीब 40 प्रतिनिधि और कई पत्रकार शामिल हुए। इसका आयोजन ईसीओएसओसी से मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था सोसाइटी ऑफ थ्रीटेंड पीपुल ने किया था।

स्विट्जरलैंड में जेनेवा स्थित परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि कार्यालय तिब्बत ब्यूरो और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने श्री तेनजिन नोर्बू को स्विट्जरलैंड आमंत्रित किया था। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने बासेल में एक ग्रीष्मकालीन शिविर में यूरोप के तिब्बती युवा संघ के सदस्यों और तिब्बती समुदाय के अन्य लोगों को संबोधित किया। इसके बाद 25 सितंबर को वे ज्यूरिख में आयोजित चर्चा 'तिब्बत–तीसरा ध्रुव' में शामिल हुए। नोर्बू ने ग्रीनपीस स्विट्जरलैंड के अधिकारियों से भी मुलाकात की।

तिब्बती पठार पर रहने वाले 60 लाख तिब्बतियों को समस्या हो रही है बल्कि इससे भारत, चीन और अन्य पड़ोसी देशों के अरबों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन सरकार द्वारा तिब्बत पठार के यारलुंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र), ड्रि चु (यांगजे) और सालवीन नदियों पर गोपनीय तरीके से बनाए जा रहे बांधों की वजह से वियतमान, लाओस, कंबोडिया, पाकिस्तान, बर्मा और भारत में निचली धाराओं के पास रहने वाले करोड़ों लोगों और जैवविविधता पर गहरा असर पड़ेगा।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आं

1. निर्वासित तिब्बती समुदाय के बीच लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में उल्लेखनी दलाई लामा (बीच में) को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। निर्वासित ति ड्रबग्यू निमा
2. धर्मशाला में गुरुवार, 16 सितंबर को प्रातःकालीन सत्र में शामिल होने के बाद
3. मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य लोगों को निर्वासित तिब्बती जीवन से जुड़ी
4. कैम्प हेल में प्रशिक्षित तिब्बती स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कैम्प हेल में अ पताका।
5. लद्दाख के चोगलमसर में बाढ़ प्रभावित लोगों को सांत्वना देते हुए परमपावन
6. तिब्बतियों ने ताइवान में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई
7. न्यूयॉर्क में बुधवार, 22 सितंबर को वाल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल के बाहर प्रदर्शन
8. दक्षिण अफ्रीकी पार्लियामेंट में सांसदों ने तिब्बत पर बयान दिया
9. तिब्बत आंदोलन के लिए खून से हस्ताक्षर करने के एक अभियान के दौरान च अभियान से जुड़े कार्यकर्ता डॉ. महेश यादव।
10. मार्च, 2010 में दुनिया की यात्रा पर जाने की तैयारी करते लाकपा। फाइल फो

(9)

(8)

(3)

(4)

ंख से तिब्बत

य प्रयास और प्रोत्साहन के लिए तिब्बती जनता की तरफ से आभार स्वरूप परमपावन
िब्बती संसद के अध्यक्ष (बाएं) और उपाध्यक्ष (दाएं) द्वारा यह सम्मान दिया गया। फोटोः

निर्वासित तिब्बती संसद से बाहर निकलते तिब्बती प्रधानमंत्री सामदोंग रिनपोछे।
तस्वीरें दिखाते श्री ताशी फुशोक
आयोजित एक स्मारक पट्टिका अनावरण समारोह में शुक्रवार को लहराती तिब्बती पूजा

दलाई लामा।

करते तिब्बती। फोटोः हेनरी लाम–द इपोक टाइम्स

ंडीगढ़ में शनिवार, 18 सितंबर को मिस हिमाचल पूर्वा राणा (बाएं) और तिब्बत मुक्ति

टो

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

(7)

(6)

तिब्बत के पूर्व कैदी ने एक फिल्म में अपनी मातृभूमि के संघर्ष को दर्शाया

पहले छोफेल अपने जीवन की कहानी को फिल्म के रूप में सार्वजनिक करने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जेल में वे जिन अन्य साथियों से मिले हैं उनकी तुलना में उनकी पीड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा यह लगता था कि मेरी कहानी काफी छोटी है।"

(न्यूयॉर्क टाइम्स डॉट कॉम, 22 सितंबर)

न्यूयॉर्क में रहने वाले कुछ तिब्बतियों के लिए यह एक व्यस्त हफ्ता था। वे अपनी मातृभूमि पर चीनी कब्जे के विरोध में संयुक्त राष्ट्र में चीनी प्रधानमंत्री के दौरे पर विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। लेकिन जासूसी के आरोप में साढ़े छह साल चीनी कैद में बिता चुके तिब्बती फिल्म निर्माता और संगीत के महारथी नवांग छोफेल के लिए यह विरोध प्रदर्शन से ज्यादा एक महत्वपूर्ण अवसर था। शुक्रवार को छोफेल ने थिएटर में अपनी फिल्म 'टिबेट इन सांग' के प्रीमियर समारोह की अध्यक्षता की। इस फिल्म में उनकी गिरफ्तारी की कहानी दिखाई गई है जब वह तिब्बती लोक संगीत पर करीब आधा सदी के तिब्बती शासन के असर पर एक डॉक्यमेंट्री की शूटिंग के लिए वहां गए थे। इस फिल्म को दुनिया भर के कई फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिल चुका है। इसमें यह दिखाया गया है कि चीनी अधिकारी सिर्फ अपने दुष्प्रचार के लिए तिब्बती संगीत और नृत्य का इस्तेमाल करते हैं, बाकी वे तिब्बती परंपराओं के पूरी तरह दमन में लगे रहते हैं। छोफेल को साल 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की चीन यात्रा से ठीक पहले रिहा किया गया था। वे दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए और इसके साथ ही उनको रिहा कराने का एक जबर्दस्त अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन खत्म हुआ जिसमें पॉल मैककर्टनी और एनी लेनॉक्स जैसी हस्तियां शामिल हुईं। इसके कुछ महीने बाद वे न्यूयॉर्क चले गए और तबसे वे इसी शहर में शांतिपूर्ण जीवन गुजारते हुए अपनी फिल्म पूरी करने में लगे रहे। छोटे कद के मृदुभाषी, 44 साल के छोफेल ने बताया, "मैं वास्तव में व्यस्त रहना चाहता था और इससे मुझे काफी ऊर्जा मिली। इस बात को लेकर लगातार चेतना बनी रहती है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। छोफेल का जन्म 1966 में तिब्बत में हुआ था, लेकिन दो साल के बाद ही सांस्कृतिक क्रांति के दौर में उनकी मां उन्हें लेकर भारत चली गईं। वे दक्षिणी भारत के एक तिब्बती शरणार्थी बस्ती में पले–बढ़े, बाद में फुलब्राइट स्कॉलरशिप हासिल कर वरमॉन्ट के मिडलबरी कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद 1995 में अपनी डॉक्युमेंट्री की शूटिंग के लिए तिब्बत चले गए। तिब्बत की अपनी यात्रा के दो माह के भीतर ही जब वह अपने पिता से मिलने जा रहे थे उन्हें एक चौकी पर चीनी खुफिया एजेंटों ने रोका। खुफिया

अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया उनका कैमरा, नोटबुक और वीडियोटेप वगैरह छीन लिया। उन्हें बिना किसी मुकदमा चलाए जासूसी का आरोप लगाकर 18 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। वे जेल के सीखचों के पीछे भी अपना शोध जारी रखा, अपने साथी कैदियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को सिगरेट के रैपर पर लिखते रहे। उन्होंने इसे एक कामचलाउ नोटबुक बना लिया। लेकिन सुरक्षा गॉर्डों की नजर इस पर पड़ गई और उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने गीतों को रटना शुरू कर दिया। इन सब अनुभवों से छोफेल का जीवन काफी बदल गया। अपनी कैद से पहले वह आज़ाद तिब्बत आंदोलन के प्रति सिर्फ एक बौद्धिक जुड़ाव ही रखते थे। लेकिन जेल की सजा काटने के बाद वह इससे ज्यादा व्यक्तिगत रूप से जुड़ गए। डॉक्युमेंट्री में वे कहते हैं, "मैं इस संघर्ष में शामिल हो गया।" लेकिन उनकी रिहाई का आंदोलन काफी व्यापक हो गया जिसके बाद जनवरी, 2002 में चीन सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। चीनी अधिकारियों ने बहाना बनाया कि उन्हें मेडिकल पैरोल पर रिहा किया जा रहा है, लेकिन छोफेल ने कहा कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी और ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय दबावों के आगे चीन सरकार को झुकना पड़ा है। वे उन दिनों को अच्छी तरह याद करते हैं जब वे न्यूयॉर्क में एक कॉलेज स्टुडेंट के रूप में आए थे और यहां के सफल प्रवासी समुदाय के बीच अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, "यह बात मुझे संबल देती थी क्योंकि यहां आने वाले प्रवासी समुदाय के सभी लोगों के सामने एक बड़ा लक्ष्य था।" न्यूयॉर्क एर्व न्यूजर्सी के तिब्बती समुदाय के अधिकारियों के अनुसार इन दोनों शहरों में क्रमशः 5000 और 6000 तिब्बती हैं। प्रवासी अधिकारी इनके बीच समाज सेवा एवं सांस्कृतिक कक्षाएं चलाने जैसा काम करते हैं। तिब्बतियों की जनसंख्या शहर में छितराई हुई है, इसलिए मैनहट्टन के ईस्ट 32 स्ट्रीट पर स्थित एक ईमारत में इनका सांस्थानिक केंद्र बनाया गया है। इसमें सांस्कृतिक समूह का कार्यालय और दलाई लामा के अमेरिका में स्थित प्रतिनिधि का भी कार्यालय है।

पहले छोफेल अपने जीवन की कहानी को फिल्म के रूप में सार्वजनिक करने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जेल में वे जिन अन्य साथियों से मिले हैं उनकी तुलना में उनकी पीड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा यह लगता था कि मेरी कहानी काफी छोटी है।"

इस फिल्म का निर्माण साल 2009 में पूरा हुआ और इसे पिछले साल के सन डांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी का विशेष पुरस्कार हासिल हुआ। छोफेल ने हाल में दलाई लामा के न्यूयॉर्क स्थित प्रतिनिधि

लोबसांग न्यानडाक के लिए इस फिल्म का व्यक्तिगत रूप से खास प्रदर्शन किया। इसके बाद न्यानडाक ने कहा, "यह वास्तव में एक जबर्दस्त राजनीतिक संदेश देता है और इससे आज के तिब्बत की कठोर वास्तविकता की सही तस्वीर मिलती है।"

पूरे देश भर में प्रदर्शन से पहले इस फिल्म को एक हफ्ते तक सिनेमा विलेज थिएटर में प्रदर्शित किया जाएगा। छोफेल को उम्मीद है कि यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों को तिब्बत के संघर्ष के बारे में बताएगी, हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं है कि इससे तिब्बतियों के जीवन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। वह गहरी सांस लेकर कहते हैं, "हमें पिछले 50 सालों से अपने लोगों की कहानियां बताई जा रही हैं, एक तरह की कहानी शुरू से अब तक जारी है। चीनियों ने मेरे साथ यह किया, चीनियों ने मेरे साथ वह किया।" वह सवाल करते हैं, "हम इसका हल कैसे निकाल सकते हैं। मैं अपने अनुभव बांट सकता हूं और तिब्बत के अपने दोस्तों की आवाज बन सकता हूं। लेकिन क्या इससे कोई मदद मिलेगी? यह करना ठीक है, लेकिन क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? नहीं।"

चीन ने तिब्बती हवाई अड्डे पर किया अपने सुखोई का परीक्षण

(इंडियन एक्सप्रेस, 3 सितंबर, नई दिल्ली)

तिब्बत में अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ाते हुए चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने वहां वायु सेना का एक बड़ा अभ्यास किया है, जिसमें पहली बार सुखोई–30 को उड़ाया गया है। सुखाई को उड़ाकर चीन ने तिब्बत के उन्नत हवाई अड्डे का परीक्षण भी कर लिया। भारत का अनुमान है कि तिब्बत में ऐसे सात हवाईअड्डे हैं, जहां से सुखोई–30 उड़ाया जा सकता है। इनमें से दो का निर्माण हाल ही में हुआ है। सैन्य अभ्यास करीब दो महीने पहले हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी हाल ही में मिल पाई है। कुछ दिनों पहले रक्षामंत्री ए.के. एंटोनी की विस्तृत सुरक्षा समीक्षा में भी इसका जिक्र था। सुरक्षा पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति को भी इस जानकारी से अवगत कराया गया।सेना का मानना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत भी अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है।

इस साल के शुरू से ही पीएलए तिब्बत में सैन्य अभ्यास कर रहा है, वह सैन्य सामग्री ढोने में तिब्बत रेलवे की क्षमता का मूल्यांकन कर रहा है। इन सबको हालांकि अब तक नजरंदाज किया जाता रहा, लेकिन इस बार जो खास बात है वह है इस अभ्यास में वायु सेना और सुखोई –30 को शामिल किया जाना। भारत इन गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। लेकिन चिंता की बात यह है कि चीनी मंशा के बारे में कुछ भी भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता है।

तिब्बत में शीर्ष लड़ाकू विमानों के साथ चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ी

(टिबेटन रिव्यू डॉट नेट, 5 सितंबर, 2010)

ऐसी खबर है कि चीन ने तिब्बत के आसमान में चीनी सैनिकों के अभ्यास के लिए वहां सुखाई–30 जैसे शीर्ष लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। इन विमानों के परीक्षण के लिए चीन जन मुक्ति सेना (पीएलए) के अन्य इकाइयों के साथ एक संयुक्त अभियान के द्वारा हवाई पट्टियों और रनवे का हाल में नवीनीकरण किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में 3 सितंबर को छपी खबर में बताया गया है कि तिब्बत में अब ऐसी सात हवाई पट्टियां हो चुकी हैं जहां से सुखोई–30 विमान उड़ाए जा सकते हैं, जिनमें से दो का निर्माण हाल में ही हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना ने करीब दो महीने पहले इन विमानों के साथ अभ्यास किया है, हालांकि इसके बारे में जानकारी हाल में ही मिल पाई है और कुछ दिनों पहले भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी द्वारा सुरक्षा पर किए गए एक व्यापक समीक्षा में इस जानकारी को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेनाओं का मानना है कि इसमें चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि भारत ने भी अपनी क्षमताओं को बेहतर कर लिया है। वैसे तो यह केवल एक विभाग के स्तर का अभ्यास था, लेकिन इसको काफी महत्वाकांक्षी माना जा रहा है क्योंकि पीएलए ने इसके लिए तिब्बत में एक मशीनी केंद्र स्थापित कर लिया है। यह मशीनी केंद्र पीएलए के रैपिड रिएक्शन फोर्स (आरआरएफ) का हिस्सा है जिसे भविष्य में होने वाले "छोटे पैमाने के और ज्यादा तीव्रता के क्षेत्रीय लड़ाई या सैन्य अभियानों के लिए विकसित किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरआरएफ को उच्च तकनीक वाले साधनों से लैस किया गया है और इनसे जुड़े कर्मियों को खास प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें अन्य सैन्य बलों से बेहतर माना जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी आरआरएफ ने वायु सेना और एक पर्वतीय इनफैंट्री डिवीजन के साथ मिलकर ऊंचे पहाड़ों और जटिल इलेक्ट्रोमैगनेटिक माहौल में एक संयुक्त प्रतिरक्षा एवं जवाबी हमले का अभ्यास किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत के समय से ही पीएलए की तिब्बत सैन्य कमान काफी सक्रिय रहा है, उसने छोटे–छोटे अभ्यास किए, सैन्य साजोसामान ढोने के लिए तिब्बत रेलवे का परीक्षण

सुखाई को उड़ाकर चीन ने तिब्बत के उन्नत हवाई अड्डे का परीक्षण भी कर लिया। भारत का अनुमान है कि तिब्बत में ऐसे सात हवाईअड्डे हैं, जहां से सुखोई–30 उड़ाया जा सकता है। इनमें से दो का निर्माण हाल ही में हुआ है। सैन्य अभ्यास करीब दो महीने पहले हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी हाल ही में मिल पाई है।

पांच भिक्षुणियां तेनजिन थुबतेन, नवांग छोक्यी, जिग्मे यांगचेन, नवांग छोजोम और गवांग सैमड्रोल अब भी तिब्बत में हैं।

किया और नियमित रूप से होने वाले अभ्यास की आवृत्ति बढ़ा दी। अखबार से सूत्रों ने कहा है कि इस अभ्यास के ज्यादातर कार्यक्रमों पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, लेकिन जब इसमें वायु सेना और सुखाई–30 को शामिल किया गया तब जाकर सबका ध्यान आकर्षित हुआ। भारत इन सब पर गहरी नजर बनाए रखी है। भारतीय सेना ने पूर्वी सेक्टर में अपने सैन्य ढांचे को बेहतर बनाया है, तेजपुर हवाई पट्टी को सुखोई–30 के उड़ान के लायक बनाया गया है, इसलिए चीन की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया की भारतीय सैन्य बलों को उम्मीद थी, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर भारी चिंता है क्योंकि चीन के इरादे कब बदल जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता।

दो तिब्बती पत्रकारों को जेल में डाला गया

(एएफपी, 7 सितंबर, बीजिंग)

साल 2008 में तिब्बत में फैली अशांति पर सरकारी दमन के बारे में लिखने के आरोप में उत्तर–पश्चिमी चीन से दो तिब्बती पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। प्रेस की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। बुद्ध और कालसांग जिंपा नाम के इन दो पत्रकारों को क्विंघई प्रांत से क्रमशः जुलाई और अगस्त माह में ही गिरफ्तार किया गया था और उन पर 'अलगाववाद' फैलाने का आरोप लगाया गया। पेरिस स्थित संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक बयान में यह जानकारी दी है।

संस्था का कहना है कि इसके साथ ही चीन में गिरफ्तार कर जेल में डाले गए तिब्बती पत्रकारों एवं लेखकों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। इनमें से आधे पत्रकारों को चीन में हिरासत में लिया गया। संगठन ने बताया कि देश से बाहर सूचनाएं भेजने के आरोप में अन्य 50 तिब्बती नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया है।

पत्रकार द्वय को रिहा करने की मांग करते हुए संगठन ने कहा है, "मार्च 2008 के बाद से अब तक इस तरह की गिरफ्तारियां बंद नहीं हुई हैं और इस तरह से तिब्बती बुद्धिजीवियों की आवाज को व्यापक तौर पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है।" दूसरी तरफ, भारत स्थित संगठन टिबेट पोस्ट इंटरनेशनल ने भी बताया है कि इन दो पत्रकारों को तब गिरफ्तार किया गया जब इनके आलेख चीन से बाहर प्रकाशित हुए। हालांकि, जब एएफपी ने क्विंघई प्रांत की राजधानी जिनिंग की पुलिस से संपर्क किया तो उसका कहना था कि उन्हें ऐसी किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है।

उन्होंने बताया, "अधिकारी ननरी गए थे यह तसल्ली करने कि वहां मैं तो नहीं हूं। इसलिए मैं दोबारा वहां नहीं गई ताकि अन्य भिक्षुणियों को किसी तरह की परेशानी न हो।" 34 साल की तिब्बती भिक्षुणी फुंसोक निद्रोन की रिहाई के साथ ही सभी गायिका भिक्षुओं की रिहाई हो गई। कर रही हैं।

तिब्बती की 'गायिका भिक्षुणी' अपने दूसरे प्रयास में भारत पहुंची

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 21 सितंबर)

तिब्बत में 'गायिका भिक्षुणियां' (सिंगिंग नन) के नाम से मशहूर 14 तिब्बती भिक्षुणियों में से एक भागकर भारत पहुंच चुकी है। एक देशभक्ति गीत गाने की वजह से जेल में डाल दी गई यह भिक्षुणी अपनी सजा पूरी करने के बाद भागकर भारत आ चुकी है। वाशिंगटन के इंटरनेशनल कैंपेन फॉर टिबेट ने यह जानकारी दी है। संगठन के अनुसार पालदेन छोद्रोन इस साल 1 सितंबर को भारत पहुंची है और आठ साल की सजा पूरी करने के बाद यह एक बार पहले भी भारत आने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन उसमें विफल रही थी। पहले प्रयास में पकड़े जाने के बाद इसे फिर से तीन साल के लिए 'सश्रम सुधार शिविर' में डाल दिया गया था। पालदेन छोद्रोन ऐसी आठवीं गायिका भिक्षुणी है जो तिब्बत से निर्वासित होकर आई है। पालदेन का जन्म 1973 में तिब्बती राजधानी ल्हासा के निकट निमो में एक किसान परिवार में हुआ था। वह 14 साल की उम्र में ही शुंगसेब ननरी में नन यानी भिक्षुणी बन गई। तिब्बत की राजधानी ल्हासा के ल्हासा में बारखोर चौक पर हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की वजह से उसे पहली बार 1990 में गिरफ्तार किया गया और तीन साल कारावास की सजा दी गई। लेकिन जेल से रिहाई से कुछ दिनों पहले ही पालदेन उन 13 भिक्षुणियों के समूह में शामिल हो गईं जिन्होंने 1993 में अपनी जेल की कोठरी से ही देशभक्तिपूर्ण गाने की रिकॉर्डिंग की। इस गाने में दलाई लामा और तिब्बत की महिमा का बखान किया गया था और इसके द्वारा वे बाहर रहने वाले अपने परिवार एवं दोस्तों को यह बताना चाहती थीं कि द्रापची के कठोर वातावरण के बावजूद उनकी भावना को दबाया नहीं जा सकता। इन सभी 14 भिक्षुणियों को कठोर प्रताड़ना दी गई जिससे एक भिक्षुणी नवांग लोछो की मौत हो गई। चीन की एक अदालत ने पालदेन की सजा को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया। आखिरकार अक्टूबर 1998 में पालदेन को रिहा किया गया। आईसीटी से धर्मशाला में बात करते हुए पालदेन ने बताया कि चीनी अधिकारियों ने उसे ननरी में फिर से नहीं जाने दिया। उन्होंने बताया, "अधिकारी ननरी गए थे यह तसल्ली करने कि वहां मैं तो नहीं हूं। इसलिए मैं दोबारा वहां नहीं गई ताकि अन्य भिक्षुणियों को किसी तरह की परेशानी न हो।" 34 साल की तिब्बती भिक्षुणी फुंसोक निद्रोन की रिहाई के साथ ही सभी गायिका भिक्षुओं की रिहाई हो गई। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने और देशभक्ति गीत की रिकॉर्डिंग की वजह से निद्रोन को 15 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। निद्रोन

फिलहाल स्विट्जरलैंड में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। करीब 11 साल जेल में बिताने वाली नवांग सैंगद्रोल फिलहाल न्यूयॉर्क में रह रही हैं। आठ गायिका भिक्षुणियां अब निर्वासित जीवन बिता रही हैं। पांच भिक्षुणियां तेनजिन थुबतेन, नवांग छोक्यी, जिग्मे यांगचेन, नवांग छोजोम और गवांग सैमड्रोल अब भी तिब्बत में हैं।

धर्मशाला के मुख्य बौद्ध मंदिर में लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम

(टिबेट डॉट नेट, 1 सितंबर, 2010, धर्मशाला)

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बती भाषा में वेबसाइट के नए संस्करण का तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर 2 सितंबर, 2010 को लोकार्पण होगा। गप्रंदद्ध.पलमण्वतह नाम की इस वेबसाइट को उन्नत करके इसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। इस वेबसाइट में परमपावन दलाई लामा का जीवन परिचय, मानव मूल्यों, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों, तिब्बत के इतिहास, संस्कृति, भाषा और धर्म, तिब्बत पर पुस्तकें, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और उसकी गतिविधियों, तिब्बत की आंतरिक स्थिति और कई मसलों पर अद्यतन जानकारी मिलती है। इसमें एक फोटो और वीडियो गैलरी भी है। इस वेबसाइट का संचालन तिब्बत सरकार के सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के चीन डेस्क द्वारा किया जाता है।

तिब्बतियों ने लोकतंत्र दिवस की ऐतिहासिक 50वीं सालगिरह मनाई

(तिब्बत डॉट नेट, 2 सितंबर, धर्मशाला)

पूरी दुनिया में तिब्बतियों ने 2 सितंबर 2010 को पिछले 50 सालों में निर्वासित तिब्बती सरकार की प्रजातांत्रिक गतिविधियों के एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मनाया। इस अवसर पर दक्षिण भारत के कर्नाटक के बायलाकुप्पी में लुगसुम समदुप्लिंग तिब्बती शरणार्थी शिविर में निर्वासित तिब्बती सरकार ने एक भव्य आयोजन किया। आयोजन में तिब्बती लोगों ने लोकतंत्र प्रदान करने के लिए दलाई लामा को आभार के रूप में एक स्वर्ण पदक दिया। दलाई लामा ने अपने इस सम्मान के लिए तिब्बती लोगों को धन्यवाद दिया। दुनिया भर के 13 देशों के कुल 17 सांसद तिब्बतियों के लोकतंत्र दिवस के आयोजन में शामिल हुए। अंतरराष्ट्रीय अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रोत्साहन ने तिब्बतियों को सत्य और न्याय की लड़ाई में अत्यधिक मदद किया।

उन्होंने तिब्बती समुदाय से कहा कि आपके सहयोग के कारण ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तिब्बती समस्या को जानने और समझने में काफी मदद की। उन्होंने कहा, "इससे चीन के अंदर रहने वाले चीनी नागरिकों को भी तिब्बत की सच्चाई को जानने का मौका मिला। आपकी ओर से किया जा रहा सहयोग अपना फल जरूर लाएगा।" आपने बयान में कशग ने कहा कि दलाई लामा ने तिब्बतियों को एक सार्थक और वास्तविक लोकतंत्र प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि आज जो भी आज़ादी कानून के शासन और लोकतत्र के रूप में तिब्बती लोगों को मिला है, वह दलाई लामा के कारण ही मिला है। कशग ने दलाई लामा के द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों का एक ब्यौरा प्रस्तुत किया। निर्वासित तिब्बती सरकार ने कहा कि निर्वासित तिब्बती सरकार की 50 सालों की सफल लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने दुनिया के सामने चीनियों के इस आरोप की सच्चाई को जगजाहिर कर दिया है कि दलाई लामा तिब्बत में सामंतवाद लाना चाहते हैं।

कालोन ट्रिपा और संसद सदस्य के चुनाव में निर्वासित सरकार की ओर से कहा गया कि हर तिब्बती बिना किसी के बहकावे में आए अपने विवेक का उपयोग करे।

करीब 11 साल जेल में बिताने वाली नवांग सैंगद्रोल फिलहाल न्यूयॉर्क में रह रही हैं। आठ गायिका भिक्षुणियां अब निर्वासित जीवन बिता रही हैं।

मैसूर में 'निर्वासित तिब्बत की यात्रा' पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन

(टिबेट डॉट नेट, 7 सितंबर, 2010, धर्मशाला)

तिब्बती जनता की निर्वासन यात्रा और अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके लंबे समय के लगाव को दर्शाने वाली तस्वीरें 5 सितंबर को दक्षिण भारतीय शहर मैसूर में आयोजित एक दिवसीय प्रदर्शनी मे प्रदर्शित की गईं। इस प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बत संग्रहालय द्वारा भारत–तिब्बत मैत्री समाज, मैसूर के सहयोग से किया गया। भारत–तिब्बत मैत्री समाज, मैसूर के अध्यक्ष कैप्टन (रिटायर्ड) एच. राजगोपाल ने अतिथियों का स्वागत करने के बाद इस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए राज्य विधान परिषद के सदस्य श्री जी. मधुसूदन ने अपने उद्घाटन भाषण में विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि चीन सरकार किस प्रकार तिब्बत में दमन कर रही है और तिब्बती जनता किस प्रकार न्याय और आज़ादी के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष कर रही है। उद्घाटन समारोह में शामिल अन्य गणमान्य अतिथियों में महाजन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष और तिब्बत समर्थक समूह, दक्षिणी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री आर. वासुदेवमूर्ति और कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज के दक्षिणी क्षेत्र के सह–संयोजक श्री पी.के. देवैया शामिल थे। 300 से ज्यादा भारतीय, तिब्बती, विदेशी नागरिक और मीडियाकर्मियों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में कुल

दलाई लामा ने अपने इस सम्मान के लिए तिब्बती लोगों को धन्यवाद दिया। दुनिया भर के 13 देशों के कुल 17 सांसद तिब्बतियों के लोकतंत्र दिवस के आयोजन में शामिल हुए।

पुलिस ने दलाई लामा को सलाह दी है कि नए आने वाले शरणार्थियों से वे अपने महल में मुलाकात के दौरान खास दूरी बनाए रखें।

60 पैनल लगाए गए थे जिनमें निर्वासित तिब्बतियों के जीवन, चीनी शासन के तहत तिब्बती संस्कृति एवं पर्यावरण के विनाश और आज़ादी एवं परमपावन दलाई लामा से आशीर्वाद लेने के लिए तिब्बती शरणार्थियों की हिमालय पार कर आने की खतरनाक यात्रा को प्रदर्शित किया गया था। इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार और यहां की जनता का इस बात के लिए आभार प्रकट के लिए कि उन्होंने पिछले 50 साल में तिब्बतियों का उदारता से समर्थन किया है और निर्वासन में परमपावन दलाई लामा के नेतृत्व में बस्तियों, स्कूलों, अस्पतालों और मठों जैसे टिकाऊ प्रतिष्ठानों की स्थापना के तिब्बतियों की उपलब्धि को प्रदर्शित करने किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य तिब्बत के बारे में तिब्बतियों और भारतीय समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना भी था। तिब्बत संग्रहालय की प्रदर्शनी आयोजित करने वाली टीम 8 एवं 9 सितंबर को कालीगल धोंडेलिंग तिब्बती बस्ती में इस प्रदर्शनी को दिखाएगी।

निर्वासित तिब्बती सरकार को चीनी जासूसों के घुसपैठ का डर

तिब्बती सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार नेपाल होते हुए भारत में हर साल औसतन 2000 से 3000 तिब्बती शरण लेने के लिए आते थे, लेकिन इस साल धर्मशाला में ऐसे सिर्फ 200 लोग पहुंचे हैं।

(हिंदुस्तान टाइम्स, धर्मशाला, 8 सितंबर)

तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की सुरक्षा मुख्य चिंता बनी हुई है जिसकी वजह से अब निर्वासित तिब्बती सरकार को तिब्बती आंदोलन के केंद्र धर्मशाला में चीनी गुप्त एजेंटों के घुसपैठ का डर सताने लगा है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि साल 2008 में तिब्बत में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान चीन ने अपने प्रशिक्षित गुप्त एजेंटों को लगा दिया था जिसकी वजह से आंदोलन हिंसक हो गया और 150 से ज्यादा लोग मारे गए। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के आधार पर धर्मशाला पुलिस ने साल 2008 में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया था। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी से इस बात की पुष्टि होती है कि गिरफ्तार चीनी नागरिक लियु जिया पहले चीन की जनमुक्ति सेना (पीएलए) में काम कर चुका था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी से पता चला है कि तिब्बत में हुए विरोध प्रदर्शनों से पहले दो बार लियु धर्मशाला का दौरा कर चुका था। खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात थी लियु के मोबाइल फोन से हासिल बातचीत का विवरण। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि लियु ल्हासा में उच्च स्तर के चीनी सैन्य अधिकारियों के संपर्क में था। सूत्रों के अनुसार लियु ने यह बताया है कि वह ल्हासा से सड़क मार्ग से भारत आया। वह नेपाल होकर अवैध तरीके से यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंच गया। तिब्बत सरकार द्वारा आशंका जताए जाने के बाद अब स्थानीय पुलिस ने तिब्बत से भागकर भारत आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू की है, हालांकि चीन द्वारा अपनी सीमा पर सख्ती बरतने के बाद भारत आने वाले तिब्बती नागरिकों की संख्या तेजी से घटी है। तिब्बती सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार नेपाल होते हुए भारत में हर साल औसतन 2000 से 3000 तिब्बती शरण लेने के लिए आते थे, लेकिन इस साल धर्मशाला में ऐसे सिर्फ 200 लोग पहुंचे हैं। एक तिब्बती सुरक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "हमने सभी तिब्बती कल्याण अधिकारियों को यह सलाह जारी की है वे तिब्बती नागरिकों को चीनी भिक्षुओं के संभावित घुसपैठ के बारे में जागरूक बनाएं।"

पुलिस ने दलाई लामा को सलाह दी है कि नए आने वाले शरणार्थियों से वे अपने महल में मुलाकात के दौरान खास दूरी बनाए रखें। दलाई लामा अक्सर अपने महल में निर्वासित तिब्बतियों से मुलाकात करते हैं। तिब्बती सरकार ने निर्वासित तिब्बतियों को चेताया है कि वे दोरजी शुगदेन के शिष्यों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों से सावधान रहें। दलाई लामा ने दोरजी शुगदेन की पूजा पर रोक लगा दी है। दलाई लामा दोरजी शुगदेन को एक 'पवित्र आत्मा' मानते हैं और उनका दावा है कि शुगदेन से जुड़ी अनुकुलन परंपरा के अुनसार यह आत्मा भगवान बुद्ध के बराबर या उनसे उनसे ऊंची है। इस प्रकार दोरजी शुगदेन की पूजा को बढ़ावा देने का मतलब है कि एक अंधविश्वासी आत्मा पूजा से तिब्बती बौद्ध परंपरा में कमी लाना। निर्वासित तिब्बतियों का मानना है कि दलाई लामा के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए चीन शुगदेन का इस्तेमाल कर रहा है।

कालोन ट्रिपा पद दो बार से ज्यादा किसी के न रहने की नीति में कोई बदलाव नहीं

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 16 सितंबर)

तिब्बती संसद ने गुरुवार को तिब्बती चार्टर (संविधान) में उस प्रस्तावित संशोधन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि निर्वासित तिब्बती संसद के प्रधानमंत्री पद पर दो बार से ज्यादा किसी व्यक्ति के न रहने की शर्त को खत्म कर दिया जाए। यह संशोधन यदि मंजूर हो जाता तो अगले साल चुनाव में तिब्बत के मौजूदा अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव लड़ सकते थे। हालांकि, खुद तिब्बती प्रधानमंत्री ने सदन में इस प्रस्तावित सुधार पर आपत्ति करते हुए कहा था कि इससे यह निर्वासित तिब्बती लोकत्रंत के प्रगतिशील विकास के रास्ते में रोड़े का काम करेगा।

कई लोकतांत्रिक देशों की तरह निर्वासित तिब्बत के

संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकता। हालांकि इसमें संशोधन के लिए संसद में विधेयक बहुमत के द्वारा पेश किया गया था, लेकिन तिब्बती प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि सदन में इस प्रस्ताव पर बहस न किया जाए। बाद में इस प्रस्ताव पर बिना बहस के ही मतदान कराया गया और दो–तिहाई सदस्यों का बहुमत न मिलने के कारण यह प्रस्ताव खारिज हो गया। तिब्बती संसद में कुल 43 सदस्य हैं जिनमें से सिर्फ 11 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। प्रधनमंत्री रिनपोछे ने संसद में इस तरह का संशोधन विधेयक लाने की प्रकृति, उद्देश्य और समय पर भी आपत्ति की। रिनपोछे ने कहा कि प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए प्रक्रिया जोर पकड़ चुकी है, इस तरह के संशोधन के प्रस्ताव से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गलत एवं भ्रामक संदेश जाएगा। यहां तक कि यदि इस तरह का प्रस्ताव पिछले मार्च सत्र में लाया जाता तो भी काफी देर हो चुका होता। हालांकि इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों का कहना है कि 'व्यापक जन इच्छा' को देखते हुए यह लाया गया था। हालांकि, आलोचकों ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे महज सुर्खियां हासिल करने की कार्रवाई बताया ताकि आगामी चुनावों से पहले जनता का समर्थन हासिल किया जा सके। साल 2001 में प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे तिब्बत के पहले सीधे निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे, जब दलाई लामा ने 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में तिब्बती राजव्यवस्था को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास शुरू किया था। उन्होंने आह्वान किया था कि निर्वासित तिब्बतियों का एक प्रत्यक्ष तौर पर चुना हुआ नेता हो। रिनपोछे जी फिलहाल दूसरी बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। साल 2006 में हुए चुनावों में उन्हें भारी मतों से विजय मिली थी। उन्हें कुल मतों का करीब 90.72 फीसदी हिस्सा 29,000 से ज्यादा वोट मिले थे। रिनपोछे जी का कार्यकाल अगले साल अगस्त में पूरा हो रहा है। 14वीं निर्वासित तिब्बती संसद का 7 सितंबर को शुरू हुआ सत्र शुक्रवार को खत्म हो रहा है। 14वीं संसद का कार्यकाल अगले साल मार्च में खत्म हो रहा है और यह अंतिम सत्र से पहले का सत्र है।

आगामी आम चुनाव द्वारा तीसरी बार जनता द्वारा सीधे तिब्बती प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा और इस प्रकार मौजूदा कालोन ट्रिपा का उत्तराधिकारी सामने आएगा। कालोन ट्रिपा के रूप में पहली बार तिब्बत के इतिहास में कार्यकारी शक्तियों का लोकतांत्रिक हस्तांतरण हुआ था। आगामी चुनाव में 15वीं निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों का भी चुनाव होगा।

तिब्बतियों ने ताइवान में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई

(21 सितंबर, ताइपे)

दलाई लामा द्वारा निर्वासित तिब्बती समुदाय के बीच लोकतंत्र की स्थापना के 50 साल पूरा हो चुके हैं। निर्वासित तिब्बतियों के पहले प्रतिनिधि कमीशन ऑफ टिबेटन पीपुल्स डेप्यूटीज (सीटीपीडी) ने 2 सितंबर 1960 को कार्यभार संभाला था। इसे आज निर्वासित तिब्बतियों का संसद कहा जाता है। निर्वासित तिब्बती समुदाय इस दिन को ''लोकतंत्र दिवस'' के रूप में मनाते हैं।

इस दिन की याद में एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए ताइपे स्थित दलाई लामा के तिब्बत रिलीजियस फाउंडेशन ने कहा कि तिब्बती समुदाय को एक वास्तविक लोकतंत्र प्रदान करने के लिए हम दलाई लामा के प्रति आभारी हैं।

काओसंग इतिहास संग्रहालय में चल रही यह फोटो प्रदर्शनी 28 नवंबर तक चलेगी। यह दक्षिण पश्चिमी ताइवान का एक बड़ा शहर हैं।इस प्रदर्शनी में तिब्बती समुदाय शरणार्थियों के जीवन और अपनी संस्कृति को सहेजने के प्रयासों की झांकी प्रस्तुत की गई है। कुल 72 पैनल लगाए गए हैं। इनमें दलाई लामा के जीवन, निर्वासित तिब्बतियों के जीवन और निर्वासित तिब्बतियों के बीच लोकतंत्र की स्थापना को सहेजा गया है। इसमें तिब्बत की कागज की मुद्रा और सिक्के, डाक टिकट और तीन तिब्बती प्रांतों के पारंपरिक वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ व्याख्यानों और 22 डॉक्यूमेंटरी के प्रदर्शन का भी कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम ताइवानी लोगों के लिए तिब्बती मसले को समझने का एक अच्छा अवसर है और साथ ही इसमें वे निर्वासित तिब्बतियों के बीच लोकतंत्र की स्थापना के इन वर्षों में आए बदलाव को भी समझ सकते हैं।

हर पैनल पर विवरण हालांकि चीनी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन वहां स्वयंसेवी तैनात हैं जो आने वालों को विशेषकर समूह में आने वालों को अपनी ओर से हर पैनल के बारे में समझाते हैं। यह प्रदर्शनी अपनी श्रृंखला की पांचवीं कड़ी है। इससे पहले जुलाई 2009 से अब तक ताइवान के प्रमुख शहरों में ऐसी चार प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। दलाई लामा के तिब्बती रिलीजियस फाउंडेशन ने काओसंग म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री का इस आयोजन के लिए अपना परिसर देने के लिए धन्यवाद अदा किया।

(बी. रमण, श्रीलंका गार्जियन, चेन्नई, 16 सितंबर) सिंगापुर के विदेश मंत्री श्री जॉर्ज

कई लोकतांत्रिक देशों की तरह निर्वासित तिब्बत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकता। हालांकि इसमें संशोधन के लिए संसद में विधेयक बहुमत के द्वारा पेश किया गया था, लेकिन तिब्बती प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि सदन में इस प्रस्ताव पर बहस न किया जाए।

सिंगापुर ने चीन द्वारा मनोनीत पंचेन लामा का समर्थन किया

सिंगापुर के विदेश मंत्री द्वारा चीन के कार्यों को वैधानिकता प्रदान करना तिब्बती जनता की धार्मिक आज़ादी छीनने जैसा है और यह इस बात का पूर्व संकेत है कि वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बती जनता पर दलाई लामा थोपने का भी समर्थन कर सकते हैं।ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल अगस्त माह में तिब्बत का विवादास्पद दौरा करने वाले श्री जॉर्ज येओ नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की भारत सरकार की परियोजना में गहरी रुचि ले रहे हैं।

येओ ने अपने बयान से चीन, भारत और अन्य देशों में रहने वाले तिब्बती बौद्धों के बड़े वर्ग का दिल को दुखा दिया है। उन्होंने तिब्बतियों द्वारा अपनी परंपरा के अनुसार चुने गए पंचेन लामा की 1995 में चीन द्वारा गिरफ्तारी और उन पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चुने गए व्यक्ति को पंचेन लामा के रूप में थोपने के कार्य का समर्थन करते हुए इसको वैधानिकता प्रदान की है। चीन अभी तक तिब्बतियों द्वारा चुने गए पंचेन लामा को रिहा करने से इनकार करता रहा है और एक धार्मिक अगुआ के रूप में उनको कार्य नहीं करने दिया जा रहा। तिब्बती जनता पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा थोपे गए पंचेन लामा की वैधानिकता को तिब्बती और अन्य बौद्धों ने स्वीकार नहीं किया है, ऐसी स्थिति को देखते हुए चीन सरकार ने इस साल की शुरुआत से ही यह कवायद शुरू की है कि चीन के तिब्बती इलाकों में उसके द्वारा नियुक्त पंचेन लामा को मान्यता मिल सके। चीन ने अपने विदेश में अपनी छवि सुधारने के लिए इस कवायद को और तेज किया है। इस कवायद के तहत चीनी अधिकारियों ने अपने मनोनीत पंचेन लामा और श्री जॉर्ज येओ के बीच 14 सितंबर, 2010 को एक मुलाकात तय की, जब सिंगापुर के विदेश मंत्री चीन दौरे पर गए थे। ऐसी खबरें है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मनोनीत पंचेन लामा ने सिंगापुर की यात्रा पर जाने का श्री जॉर्ज येओ का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वैसे तो इसे दोनों देशों की बौद्ध जनता के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयास के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यों को वैधानिकता प्रदान करना तिब्बती बौद्धों के धार्मिक मामलों में दखल देना और उनकी परंपराओं से छेड़छाड़ करना है। चीन ने कई मौकों पर यह बात साफ की है कि जब परमपावन दलाई लामा का निधन हो जाएगा तो उनके उत्तराधिकारी का चयन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार द्वारा किया जाएगा जैसा कि वे पंचेन लामा के मामले में कर चुके हैं। सिंगापुर के विदेश मंत्री द्वारा चीन के कार्यों को वैधानिकता प्रदान करना तिब्बती जनता की धार्मिक आज़ादी छीनने जैसा है और यह इस बात का पूर्व संकेत है कि वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बती जनता पर दलाई लामा थोपने का भी समर्थन कर सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल अगस्त माह में तिब्बत का विवादास्पद दौरा करने वाले श्री जॉर्ज येओ नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की भारत सरकार की परियोजना में गहरी रुचि ले रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यों को वैधानिकता प्रदान करने की उनकी इस कोशिश की घोर निंदा की जानी चाहिए, जिससे हजारों तिब्बती अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए नालंदा पुनर्जीवन परियोजना से उनके जुड़ाव की नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है।

(लेखक भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय से अतिरिक्त सचिव पद से रिटायर हुए हैं और वह फिलहाल वह चेन्नई के इंस्टीट्यूट फॉर टॉपिकल स्टडीज के डायरेक्टर और चेन्नई सेंटर फॉर चाइना स्टडीज के एसोसिएट हैं। उनका ई–मेल पता है: seventyone2@gmail.com)